

विकसित भारत समाचार

वर्ष : 11

अंक : 240

गुवाहाटी | बुधवार, 2 अप्रैल, 2025

मूल्य : 10 रुपए

पृष्ठ : 8

VIKSIT BHARAT SAMACHAR

Regd. RNI No. ASSHIN/2014/56526

नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति को अंतिम रूप दिया जा रहा है : अमित शाह

पेज 2

अगर भारतीय उठेंगे, तो बांग्लादेश का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा

पेज 3

पंजाब : ईसाई धर्मगुरु बंजिंदर को दुष्कर्म मामले में उम्र कैद की सजा

पेज 5

विश्व मुक्केबाजी कप 2025 : लक्ष्य चाहा की हार के साथ भारत ने किया ...

पेज 7

मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान का बिहाली में शुभारंभ



बिहाली (हिस.)। असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा ने मंगलवार को बिहाली में मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान (एमएमयू) का शुभारंभ किया। यह योजना राज्य की अभियानों के व्यापक संशक्तिकरण को गति देने के उद्देश से शुरू की गई है। पहले चरण में स्वयं सहायता समूहों की 27,04,161 महिलाओं का चयन किया गया है। अपने चुनावी बाटे को पूरा करते हुए, डॉ. शर्मा ने 23,375 महिलाओं को सीधे 10 हजार रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी, जिससे वे चरण में, पहले चरण के फंड का सही उपयोग कर सकेंगे। दूसरे चरण में, पहले चरण के फंड का सही उपयोग करने के लिए एक अतिरिक्त समय दिया गया है। असम भाजपा के मुख्य प्रबन्धन मोर्ज बरुवा ने कहा कि यह पहले केवल वित्तीय सहायता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह ग्रामीण महिलाओं को गरीबी और निर्भरता की बेड़ियों

लोस में आज पेश होगा वक्फ बिल, भाजपा और कांग्रेस ने जारी किया व्हिप वक्फ विधेयक का विरोध करेगा विपक्ष

नई दिल्ली। 02 अप्रैल यानी बुधवार को लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पेश किया जाएगा। अभी तक की जानकारी के अनुसार यह बिल लोकसभा में दोपहर 12 बजे पेश होगा। बिजनेस ऐडवाइरी कमेटी की बैठक में विधेयक को पेश करने की जानकारी दी गई। लोकसभा में वक्फ विधेयक के पेश होने से पहले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और कांग्रेस ने सभी लोकसभा संसदों को बताया 02 अप्रैल को संसद में उम्मित रखने के लिए व्हिप जारी किया है। इधर, विपक्ष ने इस बिल पर चर्चा के लिए 12 घंटे के समय की मांग की है। वहाँ, वक्फ संशोधन विधेयक पर रणनीति पर चर्चा के लिए संसद में विपक्ष की बैठक शुरू हुई। बुधवार को लोकसभा में पेश होने वाले वक्फ संशोधन विधेयक से पहले कांग्रेस



ने भी अपने संसदों को व्हिप जारी किया है। और सभी को संसद में मौजूद रहने के लिए व्हिप का अपने संसदों को पेश होने वाली वक्फ संशोधन विधेयक पर होने वाली चर्चा से पहले विपक्ष ने एक बैठक बुलाई है। इस बैठक में वक्फ संशोधन विधेयक पर रणनीति पर मंथन किया -शेष पृष्ठ दो पर

मुख्यमंत्री ने इस साल की एचएस प्रथम वर्ष की परीक्षाएं रद्द करने का सुझाव दिया

गुवाहाटी। असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने शैक्षणिक केलेंडर पर चिंताओं का हवाला देते हुए इस उच्चतर माध्यमिक (एचएस) प्रथम वर्ष की परीक्षाएं रद्द करने का प्रस्ताव दिया है। सोमवार, 31 मार्च को पेसबुक



जोरहाट। लंबे समय से चल रहा असम-नगालैंड सीमा विवाद उत्तर पर पहुंच गया है, तथा पिछले कुछ सप्ताहों में हुई हिंसक घटनाओं के कारण जोरहाट जिले के मरियानी के विवासी नगालैंड में स्थानीतरण पर विचार कर रहे हैं। 31 मार्च की रात को हुआ नवीनतम हमला, मात्र 10 दिनों में तीसरी ऐसी घटना थी, जिससे स्थानीय लोगों के बाद, कथित तौर पर अपहरण व्यक्तियों को रिहा करने में भय और बढ़ गया। सोमवार की रात सीमा पार से से पहले खाली कागजों पर हस्ताक्षर -शेष पृष्ठ दो पर

असम-नगालैंड सीमा संकट बढ़ा मरियानी गांववालों को अपहरण और धमकी का सामना करना पड़ रहा है



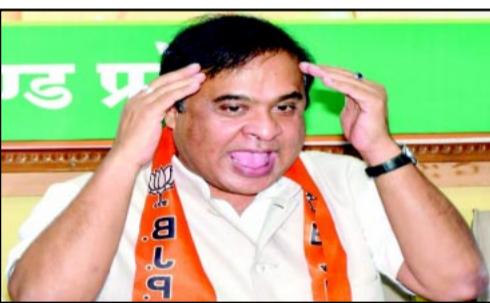
जोरहाट। लंबे समय से चल रहा असम-नगालैंड सीमा विवाद उत्तर पर पहुंच गया है, तथा पिछले कुछ सप्ताहों में हुई हिंसक घटनाओं के कारण जोरहाट जिले के मरियानी के विवासी नगालैंड में स्थानीतरण पर विचार कर रहे हैं। 31 मार्च की रात को हुआ नवीनतम हमला, मात्र 10 दिनों में तीसरी ऐसी घटना थी, जिससे स्थानीय लोगों के बाद, कथित तौर पर अपहरण व्यक्तियों को रिहा करने में भय और बढ़ गया। सोमवार की रात सीमा पार से से पहले खाली कागजों पर हस्ताक्षर -शेष पृष्ठ दो पर

सीएम ने बिजली बिल में एक रुपए प्रति यूनिट की कटौती की घोषणा की इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता



गुवाहाटी। मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने गर्मी के मौसम से पहले उपभोक्ताओं को राहत देते हुए बिजली दरों में कटौती की। एकस पर खबर शेयर करते हुए शर्मा ने लिखा कि अप्रैल आ गया है - तापमान बढ़ेगा लेकिन

मोहम्मद यूनुस के भारत-विरोधी बयान पर भड़के असम सीएम, कहा-



ग्रामीण यूनिस के भारत-विरोधी बयान पर भड़के असम सीएम, कहा-

बीरेन सिंह ने भी लगाई फटकार

इंफाल। बांग्लादेश की अंतिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के द्वारा असम-नगालैंड सीमा विवाद उत्तर पर पहुंच गया है, तथा पिछले कुछ सप्ताहों में हुई हिंसक घटनाओं के कारण जोरहाट जिले के मरियानी के विवासी नगालैंड में स्थानीतरण पर विचार कर रहे हैं। 31 मार्च की रात को हुआ नवीनतम हमला, मात्र 10 दिनों में तीसरी ऐसी घटना थी, जिससे स्थानीय लोगों के बाद, कथित तौर पर अपहरण व्यक्तियों को रिहा करने में भय और बढ़ गया। सोमवार की रात सीमा पार से से पहले खाली कागजों पर हस्ताक्षर -शेष पृष्ठ दो पर

भारत-चिली व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता करने पर हुए सहमत



गुवाहाटी। असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने मंगलवार को बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के उत्तर पर चिंता की विषय में विपक्षमें उन्हें भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को भूमि से घिरा हुआ बताया था। शर्मा ने यह भी कहा कि यूनुस की टिप्पणी भारत के रणनीतिक विकास नेतृत्व के लिए बहुत जरूरी है। विपक्षी नेताओं का दावा है कि इन मीटिंगों से बिजली का विवाद हो जाता है, जिससे जनता 1 रुपए प्रति यूनिट की घोषणा की गयी है। बांग्लादेश के राज्यों का बोर्डर विवाद के बाद दोनों नेताओं ने एक एक्सप्रोस्ट में लिखा कि बांग्लादेश की तथाकथित अंतरिम सरकार



के मोहम्मद यूनिस द्वारा दिया गया बयान, जिसमें उन्होंने पूर्वोत्तर भारत के सात बहन राज्यों को भूमि से घिरा हुआ बताया है और लिखा कि बांग्लादेश की उत्तरांतर सरकार

2028 में होगा ट्रंप-ओबामा का महामुकाबला!

अमेरिकी राजनीति में नई बहस



विशिंगटन। अमेरिकी राजनीति में इन दिनों एक नई बहस छिड़ गई है।

क्या 2028 में डोनाल्ड ट्रंप और बराक ओबामा आमने-सामने होंगे? इस चर्चा को उस बात और

बाला मिली कि बांग्लादेश द्वारा दिया गया बयान, जिसमें उन्होंने पूर्वोत्तर भारत के सात बहन राज्यों को भूमि से घिरा हुआ बताया है और लिखा है कि बांग्लादेश की उत्तरांतर सरकार

के मोहम्मद यूनिस द्वारा दिया गया बयान पर चिंता की गई है।

-शेष पृष्ठ दो पर

अमेरिका में स्वास्थ एजेंसियों पर गिरी गाज, 10000 कर्मचारियों की नौकरी खत्म



वाशिंगटन। अमेरिका के स्वास्थ और मानव सेवा विभाग की प्रक्रिया शुरू हो गई है।

यह एक एजेंसी की विभागीय अधिकारी द्वारा दिया गया है।

यह एक एजेंसी की विभागीय अधिकारी द्वारा दिया गया है।

यह एक एजेंसी की विभागीय अधिकारी द्वारा दिया गया है।

यह एक एजें



गुवाहाटी/आसपास

बुधवार, 2 अप्रैल, 2025

यूनुस को एजेपी की चेतावनी, कहा- अगर भारतीय उठेंगे, तो बांग्लादेश का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा

गुवाहाटी। बांग्लादेश का जन्म भारत की उदारता से हुआ है। एक ऐसा देश जो अपने दम पर लोकतांत्रिक चुनाव नहीं करा सकता, जहां प्रधानमंत्री भीड़ के हमलों के डर से भाग जाते हैं, उसे भारत जैसे शक्तिशाली राष्ट्र के खिलाफ बोलने का कहाँ हक नहीं है। बांग्लादेश की आपाधिकार सरकार के अंतरिम प्रमुख मोहम्मद यूनुस द्वारा चीन की यात्रा के दौरान की गई हालिया टिप्पणियों के बाद असम जातीय परिषद (एजेपी) की ओर से यह कहीं प्रतिक्रिया आई। आज एक प्रेस बयान में, एजेपी के अध्यक्ष लुनिन्योति गोपीनाथ और महासचिव जगदीप झुम्बा ने यूनुस की आतोचना करते हुए कहा कि बांग्लादेश एक



विजेता मुहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार का प्रमुख नियुक्त किया गया, जो अब अस्तित्व और आधिक ठहराव से जु़री रही है। परंपरागत रूप से, प्रत्येक बांग्लादेशी राष्ट्राध्यक्ष ने बांग्लादेश के लोकतांत्रिक अस्तित्व में देश की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करते हुए अपनी पहली विदेश यात्रा के रूप में भारत को चुना है। हालांकि, यूनुस का चीन जाने और भारत के पूर्वोत्तर हितों के खिलाफ भड़काऊ बयान देने का फैसला किसी की नज़र में नहीं आया। इस प्रतिक्रिया देते हुए, एजेपी नेताओं के कहा कि अगर पाकिस्तान की आया तो वे बैठे

मुहम्मद यूनुस को लाता है कि वह भारत को चुनावी दे सकते हैं, तो वह मूर्खों की दुनिया में रह रहे हैं। उन्होंने आगे चेतावनी दी, यदि भारत के 1.4 अब लोग अपना यूनुस बांग्लादेश की पारों मोड़ते हैं, तो वह राख सदर्शन में तब्दील हो जाएगा। भारत बांग्लादेश को अपने बारबार करते हुए, क्लिंक छोड़ हसीना को निर्वासन में जाना पड़ा, जिससे व्यापक अशांति फैल गई। इसके बाद, नोबेल पुरस्कार

एजेपी नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए बांग्लादेश को 1971 में उसकी उत्तित की याद दिलाई, जब भारत के समर्थन के कारण उसे स्वतंत्रता मिली थी। उन्होंने बताया कि पिछले साल ही बांग्लादेश में भूंयकर राजनीतिक उथल-पुथल हुई थी, जिसके कारण प्रधानमंत्री शेख यसीफ ने दूरी तरफ राज्यों को भूमिका देता हुआ क्षेत्र कहा और सुनाव दिया कि चीन के पास इस बीते में अपना बाजार स्थापित करने के अवसर है।

आरएचएसी चुनाव के लिए कल होगा मतदान, केंद्रों के लिए मतदानकर्मी रवाना

गुवाहाटी (हिंस)। राखा हासोंग स्वायत्तशासी परिषद (आरएचएसी) के चुनाव में 2 अप्रैल को मतदान होना है। इसके लिए सभी तारीखों पूरी कर ली गई है। इस चुनाव के लिए मंगलवार को मतदान केंद्रों के लिए मतदानकर्मी रवाना करना गया। राखा के 3 बैठे पर सुबह 7 बजे से दोपहर बाद 3 बजे तक मतदान होगा और 4 अप्रैल को मतदान की गणना होगी। राखा हासोंग स्वायत्तशासी परिषद की 40 सदस्यीय परिषद के 36 सदस्यों का चुनाव होने जा रहा है। अब तक चार राजनीतिक दलों ने विदेशी भड़काऊ बयान देने का फैसला किसी की नज़र में नहीं आया। इस प्रतिक्रिया देते हुए, एजेपी नेताओं के कहा कि अगर पाकिस्तान की आया तो वे बैठे

मुहम्मद यूनुस को लाता है कि वह भारत को चुनावी दे सकते हैं, तो वह मूर्खों की दुनिया में रह रहे हैं। उन्होंने आगे चेतावनी दी, यदि भारत के 1.4 अब लोग अपना यूनुस बांग्लादेश की पारों मोड़ते हैं, तो वह राख सदर्शन में तब्दील हो जाएगा। भारत बांग्लादेश को अपने बारबार करते हुए, क्लिंक छोड़ हसीना को निर्वासन में जाना पड़ा, जिससे व्यापक अशांति फैल गई। इसके बाद, नोबेल पुरस्कार

भाजपा की मासिक पत्रिका असमिया भाजपा बार्ता का अप्रैल संस्करण विमोचित

गुवाहाटी (हिंस)। असम प्रदेश भाजपा की मासिक पत्रिका असमिया भाजपा बार्ता के अप्रैल संस्करण का मंगलवार को प्रदेश भाजपा मुख्यालय, अटल बिहारी वाजपेयी भवन में भव्य विमोचन का प्रयोग किया गया। इस अवसर पर भाजपा के प्रदेश महासचिव एवं विधायक दिप्तर्जन शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। विमोचन समाप्त होने के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए दिप्तर्जन शर्मा 2025 की ग्रांथ अंदोलन वर्ष के रूप में मनाने की राज्य सरकार की पहल को रोकांकित किया। उन्होंने कहा कि साहित्य सत्य का अमिट दस्तावेज होता है, जो किसी भी प्रकार के तोड़-मरोड़ से अप्राप्तिक होता है। उन्होंने एसपी नेताओं के लिए स्वायत्तशासी परिषद के चुनाव को महत्वपूर्ण मतदानाओं की संख्या 445586 है। इसमें 216181 पुरुष और 229394 महिलाएँ हैं। मतदान केंद्रों की संख्या 630 है। सीटों में 25 एसपी के लिए और 6 महिलाओं के लिए आरक्षित रहे। उन्होंने कहा कि इस प्रकार 2 अप्रैल को ग्रांथ अंदोलन वर्ष के रूप में मनाने की राज्य सरकार की पहल को रोकांकित किया। उन्होंने कहा कि साहित्य सत्य का अमिट दस्तावेज होता है, जो किसी भी प्रकार के तोड़-मरोड़ से अप्राप्तिक होता है। उन्होंने एसपी नेताओं के लिए स्वायत्तशासी परिषद के चुनाव को महत्वपूर्ण मतदानाओं की संख्या 445586 है। इसमें 216181 पुरुष और 229394 महिलाएँ हैं। मतदान केंद्रों की संख्या 630 है। सीटों में 25 एसपी के लिए और 6 महिलाओं के लिए आरक्षित रहे। उन्होंने कहा कि इस प्रकार 2 अप्रैल को ग्रांथ अंदोलन वर्ष के रूप में मनाने की राज्य सरकार की पहल को रोकांकित किया। उन्होंने कहा कि साहित्य सत्य का अमिट दस्तावेज होता है, जो किसी भी प्रकार के तोड़-मरोड़ से अप्राप्तिक होता है। उन्होंने एसपी नेताओं के लिए स्वायत्तशासी परिषद के चुनाव को महत्वपूर्ण मतदानाओं की संख्या 445586 है। इसमें 216181 पुरुष और 229394 महिलाएँ हैं। मतदान केंद्रों की संख्या 630 है। सीटों में 25 एसपी के लिए और 6 महिलाओं के लिए आरक्षित रहे। उन्होंने कहा कि साहित्य सत्य का अमिट दस्तावेज होता है, जो किसी भी प्रकार के तोड़-मरोड़ से अप्राप्तिक होता है। उन्होंने एसपी नेताओं के लिए स्वायत्तशासी परिषद के चुनाव को महत्वपूर्ण मतदानाओं की संख्या 445586 है। इसमें 216181 पुरुष और 229394 महिलाएँ हैं। मतदान केंद्रों की संख्या 630 है। सीटों में 25 एसपी के लिए और 6 महिलाओं के लिए आरक्षित रहे। उन्होंने कहा कि साहित्य सत्य का अमिट दस्तावेज होता है, जो किसी भी प्रकार के तोड़-मरोड़ से अप्राप्तिक होता है। उन्होंने एसपी नेताओं के लिए स्वायत्तशासी परिषद के चुनाव को महत्वपूर्ण मतदानाओं की संख्या 445586 है। इसमें 216181 पुरुष और 229394 महिलाएँ हैं। मतदान केंद्रों की संख्या 630 है। सीटों में 25 एसपी के लिए और 6 महिलाओं के लिए आरक्षित रहे। उन्होंने कहा कि साहित्य सत्य का अमिट दस्तावेज होता है, जो किसी भी प्रकार के तोड़-मरोड़ से अप्राप्तिक होता है। उन्होंने एसपी नेताओं के लिए स्वायत्तशासी परिषद के चुनाव को महत्वपूर्ण मतदानाओं की संख्या 445586 है। इसमें 216181 पुरुष और 229394 महिलाएँ हैं। मतदान केंद्रों की संख्या 630 है। सीटों में 25 एसपी के लिए और 6 महिलाओं के लिए आरक्षित रहे। उन्होंने कहा कि साहित्य सत्य का अमिट दस्तावेज होता है, जो किसी भी प्रकार के तोड़-मरोड़ से अप्राप्तिक होता है। उन्होंने एसपी नेताओं के लिए स्वायत्तशासी परिषद के चुनाव को महत्वपूर्ण मतदानाओं की संख्या 445586 है। इसमें 216181 पुरुष और 229394 महिलाएँ हैं। मतदान केंद्रों की संख्या 630 है। सीटों में 25 एसपी के लिए और 6 महिलाओं के लिए आरक्षित रहे। उन्होंने कहा कि साहित्य सत्य का अमिट दस्तावेज होता है, जो किसी भी प्रकार के तोड़-मरोड़ से अप्राप्तिक होता है। उन्होंने एसपी नेताओं के लिए स्वायत्तशासी परिषद के चुनाव को महत्वपूर्ण मतदानाओं की संख्या 445586 है। इसमें 216181 पुरुष और 229394 महिलाएँ हैं। मतदान केंद्रों की संख्या 630 है। सीटों में 25 एसपी के लिए और 6 महिलाओं के लिए आरक्षित रहे। उन्होंने कहा कि साहित्य सत्य का अमिट दस्तावेज होता है, जो किसी भी प्रकार के तोड़-मरोड़ से अप्राप्तिक होता है। उन्होंने एसपी नेताओं के लिए स्वायत्तशासी परिषद के चुनाव को महत्वपूर्ण मतदानाओं की संख्या 445586 है। इसमें 216181 पुरुष और 229394 महिलाएँ हैं। मतदान केंद्रों की संख्या 630 है। सीटों में 25 एसपी के लिए और 6 महिलाओं के लिए आरक्षित रहे। उन्होंने कहा कि साहित्य सत्य का अमिट दस्तावेज होता है, जो किसी भी प्रकार के तोड़-मरोड़ से अप्राप्तिक होता है। उन्होंने एसपी नेताओं के लिए स्वायत्तशासी परिषद के चुनाव को महत्वपूर्ण मतदानाओं की संख्या 445586 है। इसमें 216181 पुरुष और 229394 महिलाएँ हैं। मतदान केंद्रों की संख्या 630 है। सीटों में 25 एसपी के लिए और 6 महिलाओं के लिए आरक्षित रहे। उन्होंने कहा कि साहित्य सत्य का अमिट दस्तावेज होता है, जो किसी भी प्रकार के तोड़-मरोड़ से अप्राप्तिक होता है। उन्होंने एसपी नेताओं के लिए स्वायत्तशासी परिषद के चुनाव को महत्वपूर्ण मतदानाओं की संख्या 445586 है। इसमें 216181 पुरुष और 229394 महिलाएँ हैं। मतदान केंद्रों की संख्या 630 है। सीटों में 25 एसपी के लिए और 6 महिलाओं के लिए आरक्षित रहे। उन्होंने कहा कि साहित्य सत्य का अमिट दस्तावेज होता है, जो किसी भी प्रकार के तोड़-मरोड़ से अप्राप्तिक होता है। उन्होंने एसपी नेताओं के लिए स्वायत्तशासी परिषद के चुनाव को महत्वपूर्ण मतदानाओ

संपादकीय

संघ के संस्कारों का सवाल

यह आरएसएस का शताब्दी-वर्ष है। करीब 24 साल बाद भारत के प्रधानमंत्री संघ मुख्यालय गए। पहले वर्ष 2000 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी संघ मुख्यालय गए थे। अब मौजूदा प्रधानमंत्री मोदी नागपुर मुख्यालय गए। भाजपा के दोनों ही प्रधानमंत्री आरएसएस प्रचारक थे, उनकी राजनीतिक-सामाजिक-वैचारिक जड़ें संघ से ही जुड़ी थीं, लिहाजा संघ की शरण में जाना स्वाभाविक है। ऐसी व्याख्याएं गलत और भ्रामक हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व को कोई चुनौती है या भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष को नेकर कोई विरोधाभास हैं अथवा संघ भाजपा से कुछ मुद्दों पर नाराज है, लिहाजा अन्वेषणों में तनाव है। भाजपा संघ का ही एक मातृ संगठन है, लिहाजा निर्देश और संस्कार संघवाले ही हैं। उन्हें चुनौती नहीं दी जा सकती या उनका विरोध करने का

पहले वर्ष 2000 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी संघ मुख्यालय गए थे। अब मौजूदा प्रधानमंत्री मोदी नागपुर मुख्यालय गए। भाजपा के दोनों ही प्रधानमंत्री आरएसएस प्रचारक थे, उनकी राजनीतिक-सामाजिक-वैचारिक जड़ें संघ से ही जुड़ी थीं, लिहाजा संघ की शरण में जाना स्वाभाविक है। ऐसी व्याख्याएं गलत और भ्रामक हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व को कोई चुनौती है या भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर कोई विरोधाभास हैं। अथवा संघ भाजपा से कुछ मुद्दों पर नाराज है, लिहाजा संबंधों में तनाव है। भाजपा संघ का ही एक मातृ संगठन है, लिहाजा निर्देश और संस्करण संघवाले ही हैं। उन्हें चुनौती नहीं दी जा सकती या उनका विरोध करने का दुस्साहस

दुस्साहस संभव नहीं है। संघ और भाजपा कें संबंध एक विराट परिवार सरीखे हैं। वे आपस में विमर्श करते हैं और फिर एक साझा निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। करीब 90 फीसदी नेता और कार्यकर्ता आरएसएस की पृष्ठभूमि के होते हैं, जो बाद में भाजपा के लिए काम करते हैं। आरएसएस में करीब 60 लाख स्वयंसेवक हैं। उन्हीं में से प्रचारक बनते हैं। जिन्हें भाजपा में भेजा जाता है, वहां वे सांसद, मंत्री और फिर प्रधानमंत्री बन सकते हैं। 1951 में जब 'जनसंघ' का गठन किया गया था, तब पार्टी प्रमुख डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अटल बिहारी वाजपेयी, सुंदर सिंह भंडारी, दीन दयाल उपाध्याय सरीखे चेहरों को आरएसएस से ही मांगा था। दरअसल आज हम संघ के स्तुतिगान के पक्ष में नहीं हैं और न ही इत्तिहास बताना चाहते हैं। कुछ संवेदनशील और राष्ट्रीय चेतना के स्तर के मुद्दे हैं, जो संघ के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, बंधुत्व, हिंदुत्व, एकता-अखंडता, सेवा-संस्कार और सामाजिकता के बिल्कुल विलोम हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधनों में यहीं बताया है-

संभव नहीं है। संघ और भाजपा के संबंध एक विराट परिवार सरीखे हैं। वे आपस में विमर्श करते हैं और फिर एक साझा निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। करीब 90 फीसदी नेता और कार्यकर्ता आरएसएस की पृष्ठभूमि के होते हैं, जो बाद में भाजपा के लिए काम करते हैं। आरएसएस में करीब 60 लाख ख्याली सेवक हैं। उन्हीं में से प्रवारक बनते हैं। जिन्हें भाजपा में भेजा जाता है, वहाँ वे सांसद, मंत्री और फिर प्रधानमंत्री बन सकते हैं। 1951 में जब 'जनसंघ' का गठन किया गया था, तब पार्टी प्रमुख डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अटल बिहारी वाजपेयी, सुंदर सिंह भंडारी, दीन दयाल उपाध्याय सरीखे वेहरों को आरएसएस से ही मांगा था। दरअसल आज हम संघ के स्तुतिगान के पक्ष में नहीं हैं और न ही इतिहास बताना चाहते हैं। कुछ संवेदनशील और राष्ट्रीय चेतना के स्तर के मुद्दे हैं, जो संघ के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, बंधुत्व, हिंदुत्व, एकता-अखंडता, सेवा-संस्कार और सामाजिकता के बिलकुल विलोम हैं।

अब यह नाजुक दौर है, जब संघ और भाजपा नेतृत्व को देश के सामने साफ करना चाहिए कि क्या उनका विचार और प्रयत्न का विनाशक वापर प्राप्त हासिल कर दी गई है?

प्रमोद भार्गव

भाजपा सांसदों ने इस मुद्दे को उठाते हुए कांग्रेस पर संविधान बदलने का आरोप लगाया। संसदीय कार्य मंत्री किरण रेतिजू ने कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने संवैधानिक पद पर बैठे हैं, कह रहे हैं कि पार्टी संविधान बदलकर मुस्लिमों को आरक्षण देगी। दरअसल कर्णटक की कांग्रेस सरकार में उपमुख्यमंत्री डीके खेवकुमार ने कहा है कि मुस्लिमों का ठेकाना चाहिए वार प्रतिष्ठत आरक्षण बरकरार रखने वाले एवं जरूरत पड़ी तो संविधान में भी बदलाव करेंगे। रेतिजू ने इस मुद्दे को भारी-भारी से संसद के दोनों सदनों में उठाया। इसे लेकर भारी हंगामा हुआ। इस मुद्दे का समर्थन करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कांग्रेस को आडे हाथ लेने पुरुष कहा कि 'कांग्रेस बाबा साहब आंबेडकर के संविधान को बदलना चाहती है, यकोंकि इसमें साफ लिखा है कि धर्म वैधान पर किसी को भी आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता है।

दृष्टि कोण

लमों को धर्म आधारित आरक्षण देने का तुशिटकरण से जुड़ा खेल निरंतर खेलती आ रही है।

मुस्लिम आरक्षण का खेल खेलती कांग्रेस

कर्नाटक में मुसलमानों को सार्वजनिक ठेकों में चार प्रतिशत आरक्षण देने के मध्ये पर

बारे प्राप्तिका जारीकरण देने का मुद्दा यह संसद में भारी हंगामा हुआ। भाजपा संसदोंने इस मुद्दे को उठाते हुए कांग्रेस पर संविधान बदलने का आरोप लगाया। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो संविधानिक पद पर बैठे हैं, कह रहे हैं कि पार्टी संविधान बदलकर मुस्लिमों को आरक्षण देगी। दरअसल कर्णाटक की कांग्रेस सरकार में उपमुख्यमंत्री डीके घिवकुमार ने कहा है कि मुस्लिमों का ठेकों में चार प्रतिष्ठाता आरक्षण बदलाव रखने के लिए जरूरत पड़ी तो संविधान में भी बदलाव करेंगे। रिजिजू ने इस मुद्दे को बारी-बारी से संसद के दोनों सदनों में उताया। इसे लेकर भारी हंगामा हुआ। इस मुद्दे का समर्थन करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कांग्रेस का आड़े हाथ लेते हुए कहा कि 'कांग्रेस बाबा साहब ऑबेडकर के संविधान को बदलना चाहती है, योंकि इसमें सफल लिखा है कि धर्म के आधार पर किसी को भी आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता है। परंतु कर्णाटक की कांग्रेस सरकार ऐसा करने जा रही है। संविधान बदलने का बयान संविधानिक पद पर बैठे ऐसे व्यक्ति ने दिया है, जिसे हल्के से नहीं लिया जा सकता है।' यही नहीं कर्णाटक में कांग्रेस के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया सरकार ने ओबीसी, एससी और एसटी के युवाओं का हक मारकर मुसलमानों को 4.5 प्रतिष्ठाता आरक्षण देने का काम किया था। जबकि हमारे संविधान में धर्म आधारित आरक्षण की कोई जगह नहीं है। अतएव इस तरह के प्रयास संविधान निर्माताओं की देष्टित से जुड़ी इच्छाओं के विरुद्ध हैं। बावजूद कांग्रेस मुस्लिमों को धर्म आधारित आरक्षण देने का त्रुटिकरण से जुड़ा खेल निरंतर खेलती आ रही है। कांग्रेस की सोच हमेशा से त्रुटिकरण और बोट बैंक की राजनीति की रही है। 2004 से 2010 के बीच में कांग्रेस ने चार बार आंध्रप्रदेश में मुस्लिम आरक्षण लागू करने की कोशिश की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जागरूकता के कारण वे अपने मंसूबे पूरे नहीं कर पाए? दरअसल यह कांग्रेस का 'पायलट प्रोजेक्ट' था, जिसे कांग्रेस पूरे देश में आजमाना चाहती थी। अल्पसंख्यक बनाम मुस्लिमों को पिछड़ा, दलित और आदिवासियों के संविधान में निर्धारित कोटा के अंतर्गत 4.5 प्रतिशत आरक्षण देने की केंद्र सरकार की मंशा हमेशा रही है। लेकिन न्यायालय के हस्तक्षेप के चलते इस

A large, dense crowd of people, predominantly men, is gathered in what appears to be an outdoor setting. Many individuals are wearing traditional white or light-colored head coverings, such as turbans or skullcaps. The crowd is diverse in age and ethnicity. In the foreground, a man in a white shirt and a blue head covering is looking towards the right. Behind him, another man in a white shirt and a pink head covering is looking towards the left. The background is filled with more people, creating a sense of a large assembly.

मंषा को पलीता लगाता रहा है। इस आरक्षण को लेकर आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालय के बाद देश की सर्वोच्च न्यायालय ने कड़ा रुख अपनाते हुए आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले के विरुद्ध दायर आपील को खरीज कर दिया था। केंद्र सरकार इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से स्थगन आदेश चाहती थी। इस मंषा के विपरीत कोर्ट ने सरकार से यह और स्पष्ट करने को कहा था कि वह बताए की उसने किस आधार पर अल्पसंख्यकों को 4.5 फीसदी आरक्षण देने का फैसला लिया? कोर्ट ने यह भी कहा था कि क्या इस तरह कोटे में उप कोटा आरक्षित करने का सिलसिला चलता रहेगा? दरअसल आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने धर्म के आधार पर आरक्षण का लाभ सर्विधान के विरुद्ध बताया था। दिसंबर 2011 के बाद से शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में ओबीसी वर्ग को 27 फीसदी आरक्षण का प्रावधान है। लेकिन केंद्र सरकार ने कुटिल चतुराई से ओबीसी के कोटे में खासतौर से मुस्लिमों को लुभाने के लिए 4.5 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने का प्रावधान कर दिया था। इसे आंध्र उच्च न्यायालय ने अस्वीकारते हुए साफ किया था कि कोटा के अंतर्गत उप कोटा दिए जाने का प्रावधान अल्पसंख्यकों को लुभाने के लिए दिया गया है। इसे कानूनी रूप देते हुए कहा गया है कि 'अल्पसंख्यकों से संबंधित' और 'अल्पसंख्यकों के लिए' जैसे वाक्यों का जो प्रयोग किया गया है वह असंगत है, जिसकी कोई जरूरत नहीं है। इस फैसले का व्यापक असर होना तय था। क्योंकि यह प्रावधान आईआईटी जैसे केंद्रीय शिक्षण संस्थानों में भी लागू हो गया था। बहरहाल न्यायालय के फैसले के बाद कांग्रेस का मुस्लिमों को लुभाने वाले नुस्खे पर पानी फिर गया था। वर्चित समृद्धय वह चाहे अल्पसंख्यक हों अथवा गरीब सर्वण, उनको बेहतरी के उचित

अवसर देना लाजिमी है, क्योंकि किसी भी बदहाली की सूरत, अल्पसंख्यक अथवा जातिवादी चश्मे से नहीं सुधारी जा सकती ? खाद्य की उपलब्धता से लेकर शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी जितने भी टोस मानवीय सरोकार हैं, उनको हासिल करना मौजूदा दौर में केवल पूँजी और शिक्षा से ही संभव है। ऐसे में आरक्षण के सरोकारों के जो वास्तविक हकदार हैं, वे अपरिहार्य योग्यता के दायरे में न आ पाने के कारण उपेक्षित ही रहेंगे। अलबत्ता आरक्षण का सारा लाभ वे बटोर ले जाएंगे जो अर्थिक रूप से पहले से ही सक्षम हैं और जिनके बच्चे पब्लिक स्कूलों से पढ़े हैं। इसलिए इस संदर्भ में मुसलमानों और भाषायी अल्पसंख्यकों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने की वकालत करने वाली रंगनाथ मिश्र आयोग की रिपोर्ट के भी कोई बुनियादी मायने नहीं रह गए थे ? यह रिपोर्ट भी मुसलमानों को संवैधानिक प्रावधानों में आरक्षण जैसे विकल्प खालने के लिए तैयार कराई गई थी। संविधान के अनुच्छेद 15 के अनुसार धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर राष्ट्र किसी भी नागरिक के साथ पक्षपात नहीं कर सकता। इस दृष्टि से संविधान में विरोधाभास भी है। संविधान के तीसरे अनुच्छेद, अनुसूचित जाति आदेश 1950 जिसे प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के नाम से भी जाना जाता है, के अनुसार केवल हिंदू धर्म का पालन करने वालों के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को अनुसूचित जाति की श्रेणी में नहीं माना जाएगा। इस परिप्रेक्ष्य में अन्य धर्म समुदायों के दलित और हिंदू दलितों के बीच एक स्पष्ट विभाजक रेखा है, जो समता और सामाजिक न्याय में भेद करती है। इसी तात्पर्य में पिछले पचास सालों से दलित ईसाई और दलित मुसलमान संघर्षत रहते हुए हिंदू अनुसूचित जातियों को दिए जाने वाले अधिकारों की मांग करते चले आ रहे हैं। रंगनाथ मिश्र की रिपोर्ट इसी भेद को दूर करने की पैरवी करती है। वर्तमान समय में मुसलमान, सिख, पारसी, ईसाई और बौद्ध ही अल्पसंख्यक दायरे में आते हैं। जबकि जैन, बहाई और कुछ दूसरे धर्म-समुदाय भी अल्पसंख्यक दर्जा हासिल करना चाहते हैं। लेकिन जैन समुदाय केन्द्र द्वारा अधिसूचित सूची में नहीं है। इसमें भाषाई अल्पसंख्यकों को अधिसूचित किया गया है, धर्मिक अल्पसंख्यकों को नहीं। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के मुताबिक जैन समुदाय को भी अल्पसंख्यक माना गया है।

एक महाकुंभी से मुलाकात

यह सुनकर वह हँसते हुए बोले,
‘यह बात तुम्हरे जैसा कोई
अधार्मिक व्यक्ति ही कर सकता है जिसे
भगवान पर भरोसा न हो। यमुना का
दूसरा नाम कालिन्दी है। पर राम जी की
गंगा कभी मैली नहीं हो सकती। भारत तो
जीता भी राम के नाम पर है और चलता
भी उसी के नाम पर है। नहीं तो इतने बड़े
देश को चलाना किसी आदमी के बस की
बात तो नहीं। हां, मोदी जी जैसा युगपुरुष
हो तो बात दूसरी है।’ मैं उनसे सहमत
होते हुए बोला, ‘लगता है आप सही कह
रहे हैं। ट्रैफिक जाम से परेशान इलाहाबाद
दो महीनों तक हफ्ता रहा। मुख्यमंत्री
योगी आदित्यनाथ सुधार लाने की दुहाई
देते रहे, पर होइहि सोइ जो राम रचि
रखा। को करि तर्क बढ़ावै साखा। अस
कहि लगे जपन हरिनाम। गई सती जहं
प्रभु सुखधाम। इस ट्रैफिक जाम के
कारण एक भी पुलिस कर्मी निलंबित नहीं
हुआ। फिर भी एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम
वगैरह पर सिर्फ अपनी भड़ास निकालने
या स्वान्तः सुखाय के लिए लोग लिख रहे
हैं। जबकि सरकार समर्थक कह रहे हैं कि
सरकार ने जो किया उतनी तो हमें उम्मीद
भी नहीं थी। मुझे लगता था कि माघ
महीना खत्म होते ही भीड़ थम जाएगी।
छंट जाएगी। पर मैं गलत साबित हुआ।
ऐसे में अगर सरकारी आंकड़ों के हिसाब
से स्नानाधियों का धर्म कंटा एक अरब
का आंकड़ा छू जाए तो अतिशयोक्ति नहीं
होगी। वह मेरी बात पर किसी बच्चे की
तरह प्रसन्न होते हुए बोले, ‘तुम्हें पता
नहीं कि तकरीबन डेढ़ सौ साल बाद आने
वाले इस महाकुंभ ने पूरे विश्व में किस
तरह भारत को गौरवान्वित होने का
अवसर दिया है। यहां तक कि अमेरिका
के राष्ट्रपति ट्रंप ने भी राष्ट्रपति पद के
लिए ली गई शपथ के बाद आयोजित
पत्रकार वार्ता में भारत के इस महाकुंभ का
जिक्र किया। उनका कहना था कि अगर

आईपीएल जैसा बेहद महंगा खेल आयोजन कराकर दुनिया को अपनी मजबूत अर्थव्यवस्था करनसर करता है। बेशक भारत विश्व की पांचवीं बड़ी अर्थव्यवस्था कर चुका है। मगर हकीकत यह है कि प्रजातंत्र के भविष्य बेरोजगार वर्ग के सितारे गर्दिश में हैं। बेरोजगारी देश में तशीशनाक मसला बह है। बेरोजगारी के अजाब ने शिक्षित वर्ग के युवाओं का आत्मसम्मान आत्मविश्वास छीन लिए हैं। चूंकि भारत में अक्सर सरकारी रोजगार वालों को ही इलमदार समझा जाता है। सियासी रहनुमाओं को उपराजिल माना जाता है। मुल्क के किसी भी निजाम में तब्दीली लाल सलाहियत युवा वर्ग में ही है। इंतखाबी दौर में हुक्मरानों को अपनी फैसले बज्य की जीनत बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत युवा वर्ग की ही है। सियासी रहनुमाओं को सत्ता के फलक तक पहुंचाने में भी युवा वर्ग अहम किरदार है। मगर इसे इच्छेकाक हक्कें या बेरोजगारी की इंतेहा, यह है कि अभिशाप बन चुकी बेरोजगारी की वजह से युवा डिप्रेशन नशाखारी व डंकी रूट के मकड़जाल में फंस चुके युवाओं के अभिशाप डिप्रेशन में हैं। विदेशों में नौकरी के हसीन ख्वाब दिखाकर युवाओं की तरीके से विदेश भेजने का डंकी रूट व कबूतरबाजी जैसा करोड़ों रुपए अवैध कारोबार लंबे समय से चल रहा है। ट्रैवल एजेंटों के राडार पर भी युवा हैं। ट्रैवल एजेंटों द्वारा फर्जी तरीके से विदेश भेजे गए ज्यादातर युवा बैरूने मुल्कों की जेलों में कैद हैं। नशा तस्करी के इलजाम में जेलों में बंद ज्यादातर युवा हैं। युवा छात्रों को डाक्टर, इंजीनियर, आर्मी ऑफिसर, पायलट, जज तथा प्रशासनिक अधिकारी बनाने का ख्वाब दिखाने वाले कोचिंग सेटरों का देश में हजारों करोड़ रुपए का कारोबार चल रहा है। कोचिंग के नाम पर लाखों रुपए फीस भरने के बावजूद प्रतियोगी परीक्षाओं में असफलता के बाद अवधि डिप्रेशन का शिकार होकर युवा छात्र आत्महत्या जैसा आत्मघाती उठा रहे हैं। उच्च शिक्षण संस्थानों में रीरिंग का साया भी युवा छात्रों के करता है। शिक्षा के नाम पर देश के हजारों छात्र प्रति वर्ष विदेशी संस्थानों का रुख करते हैं। करोड़ों रुपए की महंगी फीस से विदेशी संस्थानों की अर्थव्यवस्था को गुलजार करने वाले भारतीय छात्र विनस्तीय हमलों का शिकार होते हैं। भारतीय मूल के छात्रों तथा विदेशी काम करने वाले युवाओं की हत्याएं की जाती हैं। दहशतगर्दी को रखने के लिए आतंक के आकाओं को सबसे ज्यादा जरूरत युवा वर्ग अलगाववाद व चरमपंथ की आग भड़काने के लिए भी युवाओं को ही बनाया जाता है। हमसाया मुल्क पाकिस्तान की खुफिया आईएसआई भारत में अराजकता का माहौल पैदा करने के लिए 'हार्ड लाइन' के जरिए जासूसी के लिए भारतीय युवाओं को अपने फैसलों से बचाती है। हनी ट्रैप एक ऐसी साजिश है जिसमें महिला जासूस इस्तेमाल करके देश की कई संवेदनशील जानकारियां हासिल की जाती हैं।

भारत पैगम शुमार युवा चुकी मान व र करने आलिम आने की संयासी गति है। वर्ग का मसला न में है। भावक जो फर्जी पए का है। भारत वाद व कदम पीछा शिक्षण शिक्षण देशों में देशों में जीवित की है। मोहरा एंजेसी नीट्रैप' जाल में सों का आती है।

ही नीट्रैप के एंजेटों के निशाने पर भी ज्यादातर बेरोजगार युजाल सोशल मीडिया के जरिए फैलाया जाता है। सोशल बड़ा शिकार भी युवा वर्ग ही है। कई विभागों के अहलकार तथा बेरोजगार युवा ही नीट्रैप का शिकार होकर सलाखों में संगीन वारदातों के बढ़ते ग्राफ का सबव भी बेरोजगार कल्पना जैसी संगीन वारदातों को अंजाम देने के लिए गैंगस्टर युवा शूटरों की जरूरत रहती है। गैंगस्टर व शूटर बन खालिश में मौत से बेरवाह होकर युवा अपना मुस्तकबिल है। इनखाबी दौर में युवाओं के बेहतर मुस्तकबिल के लिए जाते हैं। लेकिन सियासत का किरदार कभी मुख्लिस नहीं हासिल होने के बाद तर्ज-ए-सियासत का मिजाज बदलोंगों को हुक्मरानों के दीदार दुर्लभ हो जाते हैं। बेरोजगार नशाखोरी जैसे संवेदनशील मसले सियासत के मरकजी मगर जाति-मजहब की तर्जुमानी करने वाली सियासत महिमामंडन व अरक्षण के चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकल सकती। मजदूर व बेरोजगार युवाओं की आजिजी पर चर्चा नहीं। तकदीर को कोस रहे बेरोजगार युवा महांगई की मार इन्हीं निहायत जरूरत है। डंकी रुक्मिणी निजाम से निपटें, व्यवस्था करें, अपनी डिप्रियां हाथों में पकायालयों की तवाफ करें, चुनाव करें या मुकद्दर पर यकीन करें या जुस्तजू में बैरुने मुल्कों में मुकद्दर बेरोजगारों के रंज-ओ-करने के लिए सियासी नजीबी निहायत जरूरत है। डंकी रुक्मिणी द्वारा देखा गया दृग्गम माफिया, दहशतगर्दी, गैंगस्टरों व उनी ट्रैपर चरमपंथी ताकतों का नेटवर्क बेरोजगार युवाओं की नशाखोरी, डंकी रुट व ही नीट्रैप जैसे घड़यांत्रों ने युवाओं को अपराधियों की फैफरिस्त में शामिल कर दिया। साथ तमाम तोहमते भी बेरोजगारों का ही पीछा करती गुनाहगार के नजरिए से देखा जाता है। हमारे मुल्क का अंग्रेजों द्वारा बनाया गया है। अदालतों में आरोपियों का होने में मुद्रते गुजर जाती है। ताजिरात-ए-हिंद के पैदावरें में माहिर आईन के मुनाजिरों से इंसाफ की आपाती की चश्म-ए-पलक की रौशनी छिन जाती है। न्याय की चौखट पर तारीख पे तारीख मिलती है। जम्हूरियत की पहांगामों की भेट चढ़ जाते हैं। सियासी निजाम से आश्रितः राष्ट्र के बेशकीयी सरमाया युवा वेग की ऊर्जावान करनी होगी। समाज को अपराधमुक्त बनाने के लिए युवा मुहैया कराकर स्वावलंबी बनाने के प्रयास होने चाहिए। हाथकर उन्हें खेल की ओर मोड़ना होगा।

वाहै। हनी ट्रैप का मेंडिया का सबसे बुया अधिकारी के पीछे है। समाज इनी है। अपहरण व टरों को बेरोजगार ने की कतिलाना बल बर्बाद कर रहे तए, कई बादे किए थीं होता। इख्तिदार ल जाता है। आम नगारी, महांगाई व मुदे बनने चाहिए, त आक्रांताओं के पारही। किसान-होती। गर्दिश-ए-झेले, भ्रष्टाचार से थाओं की मिन्नतें कड़ कर रोजगार वादों पर भरोसा रहे? रोजगार की उहाजिर बनने को गम को महसूस गर-ए-करम की ट, कबूतरबाजी, जैसे फॉड तथा तलाश करता है। सैकड़ों बेरोजगार या है। साजिशों के होते हैं। आरोपियों को अदालती निजाम दे बेगुनाह साखित रोकार व कानूनी स में अभिभावकों देवी के मंदिरों की चंचायतों के सेशन वासन मिलते हैं। तातकत की पैरवी वार्ग को रोजगार दइ। नशाखोरी से

कपर, ड्राइवर सड़क पर और 40 स्कूली बच्चों से भरी दसे की ओर निकल पड़ी, लेकिन ऊपरी शिमला के एक ताने ने ब्रेक लगाकर प्रदेश की हर सुर्खी बटोर ली। इस क्षणे में, चैतन्य भाव, बहादुरी का अंदाज और कुछ कर दिखाना : एक ऐसी अनुकरणीय कहानी लिख गया, जो किसी पाठ्यक्रम में भी नहीं। उधर सदन में चारित्रिक खोट निकालने की प्रवृत्ति ने अभी, लेकिन सफर पर निकले हिमाचल को अंततः सड़क पर जा रहा है। हम आर्थिक संसाधनों की खराब बस पर अनियन्त्रित हानी में ब्रेक लगाना भूल गए। क्या इसी बस पर सवार जाने के असुरक्षित सफर को किसी दिशा में ले जाने के लिए अलग पाएगी। हम व्यवस्था को कोसते हैं, लेकिन इसी व्यवस्था में हमें हकीकत रक्की रक्की प्राथमिकताएं तय करनी होंगी। इसी परिप्रेक्ष्य में देखा दरवाजे इतने बढ़ गए कि हिमाचली अस्तित्व की बस अपनी शिकार हो गई। सदन में कई बार जो बोलता, सड़क पर जहां सड़क बोल रही है, सदन की कार्यवाही नहीं सुन सकती। कुछ युवाओं ने मुंडन करवा लिया। मुंडवा दिए सिर के हांस, लेकिन शंका यह कि खबर होगी नहीं। बीबीएन की साथी यात्रियों की ही नहीं, यात्रियों की भी चूल्हे हिल जाती हैं, छोड़कर इसी मांग पत्र लिखे गए, दरखास्तें बनी होंगी, लेकिन सफर के अंत में और बजट से निकले अर्थ को फुर्सत नहीं कि कुछ अगर व्यवस्था मुंडन से जागने लग, तो हजामत में कुर्ता-पंडी वकालत हो जाएगा। हम चाहते हैं हर कुछ, हमारे सिर नाए, लेकिन नागरिक अपेक्षाओं के सिर-धड़ी की बाजी नापा के आक्रोश तक पहुंच गई। मुंडन तो हिमाचल को रहा है। विधानसभा का पूरा सत्र और सत्र के बाहर विषय की इसी बात पर निकल गया कि राज्य के 'बाल' आखिर कौन-सी शक्तियां हैं जो पहाड़ों को समतल बना पा रही हैं? सड़क है, जहां से हर दिन एक साथ कई नई जेसी बालों का पत्र के साथ हिमाचल की हजामत करने आ रही हैं। आप सदन में मंत्री महोदय के पास आंकड़े होते हैं कि प्रदेश में बदन बढ़ गया या ग्रामीण आर्थिकी तरकी कर गई, मगर वह अहरी प्रदेशों से उपभोक्ता वस्तुओं से लदे ट्रकों की कतार नहीं ही है। 'लेटे पर रखी ब्रेड, तबे पर चपाती का आटा और कुछ बासमती का झाड़ हमारे खेत से तो नहीं आया। हमारे खेत तक आता है, वह उपरे हर दाने और मूली को उखाड़ हमीं से पूछते हैं। ब्रेत की मूली हो।' हमारा खेत अगर मूली के भी काबिल नहीं होता है, तो किसान अब अपने खेत से नहीं, मुफ्त कई अन्य जिलों का किसान अब अपने खेत से नहीं, मुफ्त पेट भर पा रहा है, तो किस्सा किस सदन से सुनें।



अमेरिकी फर्म की रिपोर्ट में सोने की कीमत में बड़ी गिरावट की आशंका, फिलहाल ॲॉल टाइम हार्ड पर पहुंचा हुआ है सोना

नई दिल्ली

अमेरिकी अर्थव्यवस्था की अनिश्चितता, ट्रेड वार्स शुरू होने का डर और वैश्विक स्तर पर महानांग बढ़ने की अपेक्षा की वैश्विक स्तर पर पहुंच का कारोबार कर रहा है। अनेक वाले दिनों में इस चमकीली धारु में और तेजी आने की फ़ाइंसियल सर्विस जारी है और अमेरिकी फर्में ने अपने एक एनालिसिस में अनेक वाले सालों में सोने के भाव में जोरदार गिरावट

अनेक वाले सोने की कीमत में 35 से 38 प्रतिशत तक की गिरावट आ सकती है।

अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना 3,148.89 डॉलर प्रति ऑंस के ॲॉल टाइम हार्ड लेवल पर पहुंचा हुआ है। इसी तरह घेरे सराफा बाजार में भी सोना अभी एक अमेरिकी

फर्म ने अपने एक एनालिसिस में अनेक वाले

पटक शांत नहीं होगी, तब तक सोने के भाव में इसी तरह तेजी का रुख बना रहेगा। बाजार की अनिश्चितता के कारण निवेशक फिलहाल सेफ इन्वेस्टमेंट्स के रूप से सोने में पैसा लगाना अब भी जोरदार तेजी के कारण दुनिया पर में इसकी माझिनिंग में भी तेजी आ गई है। चीन, रूस, अस्ट्रेलिया, कनाडा और पूर्व जैसे कई स्वर्ण उत्पादक देशों में पिछले 1 साल की अवधि में सोने के उत्पादन में 40 से 52 प्रतिशत तक की बढ़ाती कर रही है।

करके सबको चौंका दिया है। इस अमेरिकी फर्म का कहना है कि सोने की कीमत गिर कर 1,780 डॉलर से लेकर 1,820 डॉलर प्रति ऑंस तक पहुंच सकती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सोने की कीमत में आई जोरदार तेजी के कारण दुनिया पर में इसकी माझिनिंग में भी तेजी आ गई है। चीन, रूस, अस्ट्रेलिया, कनाडा और पूर्व जैसे कई स्वर्ण उत्पादक देशों में पिछले 1 साल की अवधि में सोने के उत्पादन में 40 से 52 प्रतिशत तक की बढ़ाती कर रही है।

न्यूज़ब्राफ़

कानूनीयल गैस सिलेंडर 44.50 रुपये तक हुआ सस्ता, नई दरें लागू



नई दिल्ली। नए वित्त वर्ष के महीने की पहली तारीख कुछ लोगों के लिए रहत होकर आई है। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल एवं गैस विपणन कंपनियों ने कॉमर्सियल गैस सिलेंडर की कीमतों में 44.50 रुपये तक की कटौती घोषित की है। नई दरें लागू हो गयी हैं। इडियन ऑयल की बेसिस ट्रायल के मुताबिक 19 फिलिपिन गैस की कीमत 1755.50 रुपये प्रति सिलेंडर 44.50 रुपये तक सरकार 1762 रुपये प्रति सिलेंडर हो गई है। पहले ये 1803 रुपये में मिल रहा था। कोई बोलता था कि इसका दाम 44.50 रुपये तक 1921.50 रुपये में मिल रहा है, जो महले 1913 रुपये में मिल रहा था। इसी तरह देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में कॉमर्सियल गैस की कीमत 1755.50 रुपये प्रति सिलेंडर से 42 घटकर रुपये 1713.50 रुपये हो गया है। इसके अलावा चेन्नई में कॉमर्सियल गैस सिलेंडर 44.50 रुपये तक सरकार 1868.10 रुपये का लिए एवं महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई है।

डिजिटल भुगतान में भारत को वैश्विक अग्रणी बनाने में आरबीआई की भूमिका अहम : राष्ट्रपति

नई दिल्ली/मुख्य

राष्ट्रपति दौर्पति मुर्मुने ने मंगलवार को कहा कि 'विकासित भारत 2047' का निश्चय एक ऐसे वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र की मांग करता है, जो नवोजीवी, अनुकूलनीय और सभी के लिए सुलभ हो। उन्होंने कहा कि आरबीआई ने भारत को डिजिटल भुगतान में वैश्विक अग्रणी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

मुर्मुने ने रिपोर्ट बैंक और ईडिया (आरबीआई) की 90वां वर्षांग के समापन समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति मुर्मुने ने कहा कि केंद्रीय बैंक के रूप में अरबीआई भारत के लिए एक विश्वास गाथा के केंद्र में है। आरबीआई के पिछले 90 वर्षों की उल्लेखनीय यात्रा की सराहना करते हुए उन्होंने इस बात जो दिया कि सभी के वाले सुलभ वित्तीय परिवेश तंत्र 'विकासित भारत 2047' के लिए एक महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि रिजर्व बैंक ने डिजिटल भुगतान में वैश्विक अग्रणी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

उन्होंने कहा कि मौद्रिक और वित्तीय स्थिरता के रूप में अरबीआई इस यात्रा में एक निर्णायक भूमिका निभाया। इसका अनुभव अरबीआई ने अपने लोगों की नीतिक्रियाएँ बढ़ावा देने और हाथों पर वित्तीय परिवेश के रूप में विश्वास की रक्षा करना शामिल है। राष्ट्रपति ने कहा कि आरबीआई ने केवल बदलते समय के साथ विकासित हुआ है, बल्कि भारत के वित्तीय परिवर्तन का एक प्रमुख वातनुकार भी हो रहा है।

उन्होंने आगे कहा कि प्रायोगिकी के तेजी से विकास के साथ वित्तीय धोखाधड़ी और सावधार खतरों का जोखिम भी बढ़ रहा है। इस बढ़ी चिंता के लिए निन्तर संस्करण की जरूरत है। इसके लिए आरबीआई सक्रिय करने उठा रहा है, सुरक्षा उपायों को मजबूत कर कर रहा है और विश्वास बढ़ावा देने की जरूरत है।

राष्ट्रपति ने कहा कि आरबीआई ने पिछले कुछ वर्षों में नावांड, आईबीबीआई, सिड्नी और राष्ट्रीय आवास बैंक जैसी प्रमुख संस्थाओं की स्थापना करके देश की वित्तीय परिस्थितिकी तंत्र को मजबूत किया है।

राष्ट्रपति ने कहा कि आरबीआई ने अपने लोगों को वित्तीय धोखाधड़ी के तेजी से विकास के साथ वित्तीय धोखाधड़ी और सावधार खतरों का जोखिम भी बढ़ रहा है। इस बढ़ी चिंता के लिए निन्तर संस्करण की जरूरत है। इसके लिए आरबीआई सक्रिय करने उठा रहा है, सुरक्षा उपायों को मजबूत कर कर रहा है और विश्वास बढ़ावा देने की जरूरत है।

राष्ट्रपति ने कहा कि आरबीआई ने अपने लोगों को वित्तीय समावेश को मजबूत कर कर रहा है।

राष्ट्रपति ने कहा कि आरबीआई ने अपने लोगों को वित्तीय समावेश को मजबूत कर कर रहा है।

राष्ट्रपति ने कहा कि आरबीआई ने अपने लोगों को वित्तीय समावेश को मजबूत कर कर रहा है।

राष्ट्रपति ने कहा कि आरबीआई ने अपने लोगों को वित्तीय समावेश को मजबूत कर कर रहा है।

राष्ट्रपति ने कहा कि आरबीआई ने अपने लोगों को वित्तीय समावेश को मजबूत कर कर रहा है।

राष्ट्रपति ने कहा कि आरबीआई ने अपने लोगों को वित्तीय समावेश को मजबूत कर कर रहा है।

राष्ट्रपति ने कहा कि आरबीआई ने अपने लोगों को वित्तीय समावेश को मजबूत कर कर रहा है।

राष्ट्रपति ने कहा कि आरबीआई ने अपने लोगों को वित्तीय समावेश को मजबूत कर कर रहा है।

राष्ट्रपति ने कहा कि आरबीआई ने अपने लोगों को वित्तीय समावेश को मजबूत कर कर रहा है।

राष्ट्रपति ने कहा कि आरबीआई ने अपने लोगों को वित्तीय समावेश को मजबूत कर कर रहा है।

राष्ट्रपति ने कहा कि आरबीआई ने अपने लोगों को वित्तीय समावेश को मजबूत कर कर रहा है।

राष्ट्रपति ने कहा कि आरबीआई ने अपने लोगों को वित्तीय समावेश को मजबूत कर कर रहा है।

राष्ट्रपति ने कहा कि आरबीआई ने अपने लोगों को वित्तीय समावेश को मजबूत कर कर रहा है।

राष्ट्रपति ने कहा कि आरबीआई ने अपने लोगों को वित्तीय समावेश को मजबूत कर कर रहा है।

राष्ट्रपति ने कहा कि आरबीआई ने अपने लोगों को वित्तीय समावेश को मजबूत कर कर रहा है।

राष्ट्रपति ने कहा कि आरबीआई ने अपने लोगों को वित्तीय समावेश को मजबूत कर कर रहा है।

राष्ट्रपति ने कहा कि आरबीआई ने अपने लोगों को वित्तीय समावेश को मजबूत कर कर रहा है।

राष्ट्रपति ने कहा कि आरबीआई ने अपने लोगों को वित्तीय समावेश को मजबूत कर कर रहा है।

राष्ट्रपति ने कहा कि आरबीआई ने अपने लोगों को वित्तीय समावेश को मजबूत कर कर रहा है।

राष्ट्रपति ने कहा कि आरबीआई ने अपने लोगों को वित्तीय समावेश को मजबूत कर कर रहा है।

राष्ट्रपति ने कहा कि आरबीआई ने अपने लोगों को वित्तीय समावेश को मजबूत कर कर रहा है।

राष्ट्रपति ने कहा कि आरबीआई ने अपने लोगों को वित्तीय समावेश को मजबूत कर कर रहा है।

राष्ट्रपति ने कहा कि आरबीआई ने अपने लोगों को वित्तीय समावेश को मजबूत कर कर रहा है।

राष्ट्रपति ने कहा कि आरबीआई ने अपने लोगों को वित्तीय समावेश को मजबूत कर कर रहा है।

राष्ट्रपति ने कहा कि आरबीआई ने अपने लोगों को वित्तीय समावेश को मजबूत कर कर रहा है।

राष्ट्रपति ने कहा कि आरबीआई ने अपने लोगों को वित्तीय समावेश को मजबूत कर कर रहा है।

